JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 12 AUGUST TO 18 AUGUST 2020 • VOLUME- 3 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

यही पैगाम हमारा

देश को आजादी यूं ही खेल.खेल में नहीं मिल गई थी। इसके लिए देश को 1857 में क्रांति लाना पड़ी थी। उस क्रांति के लिए भी सालों तैयारी करनी पड़ी होगी। झांसी की रानी से तांतिया टोपे तक न जाने कितने देश भक्तों ने अपना शौर्य का इतिहास अपने लहू से लिखा होगा। फिरंगियों के अत्याचार से भी आजादी की चाहत कभी दफन नहीं हुई बल्कि देश भक्तों के जुनून की चिंगारी सदैव सुलगती रही। हिन्दोस्तानी लहू उबलता रहा। भगत सिंह, चन्द्र शेखर आजाद, लाला लाजपत रायए सुखदेव, राजगुरु जैसे इंकलबियों के अतिरिक्त नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज भी आजादी के लिए देशभक्तों के जुनून का बिगुल था। नेता जी ने जब यह नारा लगाया कि तुम मुझे लहू दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेता जी की इसी ललकार ने आजद हिन्द के लिए आत्म बलिदानियों की फौज खड़ी कर दी थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आन्दोलन में जब पूरा हिन्दोस्तान ही कूद पड़ा तो अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयार हो गए। मोती लाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू व उनकी प्रिय दर्शिनी बेटी इंदिरा गांधी तक अपने परिवारिक सुखों को त्याग कर आजादी की जंग में उतर गए थे। अत्याचारों का कहर झेल कर भारत ने एकजुट हो कर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा तो जाते-जाते भी वे फूट व नफरत के बीज पाकिस्तान के रूप में बीज गए जिससे भारत को आजादी के साथ बंटबारे की भयंकर तबाही भी झेलनी पड़ी। लगभग लाख लोगों को बेघर हो कर शरनार्थी शिविरों में दुर्दिन बिताने पड़े। ऊपर से कश्मीर समस्या भारत की झोली में आन पड़ी। आजादी की क्या और कितनी कीमत हमारे देश को झेलनी पड़ी इसका ब्योरा हमारे बुजुर्गों के सीने में जख्मों के साथ आज भी गुदा हुआ है।? आजादी कभी भी भीख में नहीं मिलती बल्कि इसे बाजुओं के जोर से हासिल करना पड़ता है।? हर बात में दूसरों पर निर्भर रहने वाले ही गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाते हैं। आत्मनिर्भरता के बिना आजादी संभव नहीं। अराजकता, अनुशासन हीनता में निरंकुश होने से भी आजादी कब लापता हो जाए कोई नहीं जानता। आज भी आतंकवाद की सबसे बड़ी चुनौती हमारी आजादी के समक्ष है।

अतुल शर्मा

आजादी कभी भी भीख में नहीं मिलती बल्कि इसे बाजुओं के जोर से हासिल करना पड़ता है।? हर बात में दूसरों पर निर्भर रहने वाले ही गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाते हैं।

हमारी आन्तरिक सुरक्षा हमारी अखंडता और हमारा राष्ट्रीय गौरव आतंकवाद के आमने सामने है। आतंकवाद का सिर कुचल कर ही अपनी आजादी की रक्षा हम कर कते हैं। इसके लिए हर धर्म व जाति के हर हिन्दोस्तानी को एकजुट हो कर आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा। यही पैगाम हमारा है।

ऐसे मनाएं आज़ादी का जश्न

15 अगस्त महज एक तारीख नहीं है, बल्कि हर भारतीय इस खास दिन से अपना एक अलग जुड़ाव महसूस करता है। आखिरकार देश की आजादी का जश्न ना मनाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमूमन इस खास दिन लोग अपनी फैमिली के साथ एक छोटी ट्रिप प्लॉन करते हैं। लेकिन इस बार जब पूरे देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय अपनी आजादी के जश्न को ना मनाएं।

कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय अपनी आजादी के जश्न को ना मनाएं

ऐसे में बेहतर होगा कि आप इस बार देश के माहौल को देखते हुए घर पर रहकर की इस खास दिन को सेलिब्रेट करें। आप परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। अगर संभव हो तो आप अपनी कॉलोनी में यह कार्यक्रम करें, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम करते समय सोशल डिस्टेंसिंग व सुरक्षा के अन्य मानकों का ध्यान भी जरूर रखें। मास्क पहनने जैसे सरकार के नियमों का पालन जरूर करें। अनजानी वस्तुएं हरगिज न छुएं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए आपको हाथ धोने और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह भी सरकार द्वारा दी गई है। इसके साथ आप घर में कुछ देशभक्ति के गाने बजाएं और खाने-पीने का प्रोग्राम भी रखें। इस तरह आजादी की शाम आपके लिए एक यादगार शाम बन जाएगी।

शहर की लोकल पुलिस जबरदस्ती सारे बोर्ड लगवाती-नैशनल हाईवे विभाग

जालंधर ब्रीज में प्रकाशित खबर के बाद पी.ए.पी. फ्लाईओवर पर निजी अस्पताल द्वारा लगाए गए बोर्ड उतरवाए

28.07.2020.

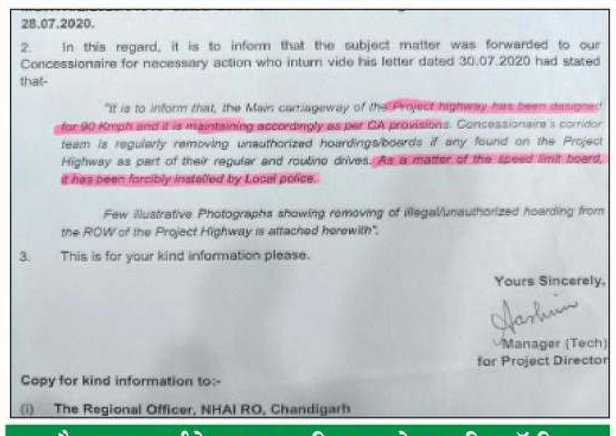

2. In this regard, it is to inform that the subject matter was forwarded to our Concessionaire for necessary action who inturn vide his letter dated 30.07.2020 had stated that-

"It is to inform that, the Main carriageway of the Project highway has been designed for 90 Kmph and it is maintaining accordingly as per CA provisions. Concessionaire's corridor team is regularly removing unauthorized hoardings/boards if any found on the Project Highway as part of their regular and routine drives. As a matter of the speed limit board, it has been forcibly installed by Local police.

Few illustrative Photographs showing removing of illegal/unauthorized hoarding from the ROW of the Project Highway is attached herewith".

3. This is for your kind information please.

Yours Sincerely,

Manager (Tech)
for Project Director

Copy for kind information to:-

(i) The Regional Officer, NHAI RO, Chandigarh

नैशनल हाईवे द्वारा जारी दस्तावेज की कॉपी।

जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

जालंधर ब्रीज द्वारा कुछ दिन पहले नैशनल हाईवे विभाग से ईमेल द्वारा पूछा गया था की उन्होंने किस नोटिफिकेशन के अधीन एक निजी हस्पताल द्वारा 50 किलोमीटर स्पीड के बोर्ड लगवाए गए है जब की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवे को छोड़ कर नैशनल हाईवे पर 90 किलोमीटर स्पीड सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है इसका जवाब देते हुए नैशनल हाईवे विभाग ने लिखित में माना है की शहर की लोकल पुलिस जबरदस्ती सारे बोर्ड लगवाती है और हमें मजबूर होकर यह बोर्ड लगाने पड़ते है। जालंधर ब्रीज द्वारा ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों से बात की गई और उन्होंने जालंधर नैशनल हाईवे पर लगे सारे गलत बोर्ड जोकि एक निजी अस्पताल द्वारा लगाए गये थे उनको उतरवा दिया गया और जालंधर ब्रीज को आश्वासन दिया की भविष्य में भी जो गलत स्पीड लिमिट के बोर्ड लगवाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी ।

छाया : रवि

किस नोटिफिकेशन के आधीन पी.ए.पी.फ्लाईओवर पर वाहनों की डिजाइन स्पीड लिमिट को बदला गया?

ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

जालंधर ब्रीज। जालंधर पानीपत-राष्ट्रीय राजमार्ग को गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाए केंद्र की सरकार। प्रधानमंत्री की इमानदारी अपने ही केंद्र के नेशनल हाईवे विभाग में विफल हो गई ये कोई भी दावा बगैर तथ्यों के साथ नहीं कीया जा रहा इसकी हकीकत आपको ग्राउंड जीरो में जाकर इस राजमार्ग के लंबित चल रहे निर्माण कार्यों को देख कर खुद ही पता चल जाएगा।

यह प्रोजक्ट पिछले तकरीबन 14 वर्षों से लंबित पड़ा है और यह अभी भी आने वाले 4 से 5 वर्षों में पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा इसके लिए ना तो प्रधानमंत्री या इस विभाग के मंत्री की कुशलता पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्यूंकि इन्होंने पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में देश के कई प्रोजेक्टों को पूरा कर दिखाया।

परन्तु इस राष्ट्रीय राजमार्ग की देरी के लिए सीधे तौर पर भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेवार है जिन्होंने ठेका प्राप्त कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिये सरकार में रह कर अपने पद का दुरूपयोग किया और करोड़ों रुपये की बेनामी सम्पति बनायीं और ठेका कंपनी को बी ओ टी मॉडल में इस प्रोजेक्ट में रख-रखाव के नाम पर करोड़ों रुपये के टोल टैक्स की आम लोगों से वसूली करवाकर बदले में लोगों को बनती सुविधाओं से वंचित रखने का काम किया।

आज भी हाईवे की हालत इतनी दयनीय है की जगह जगह पर बरसाती पानी जमा होने से लोगों की मौत हो रही है, नालियां टूटी पड़ी है।

पी.ए.पी. फ्लाईओवर को शुरु होने के 2 घंटे के बाद ही बंद करना पड़ा था जिसको अब इस गलत बने फ्लाईओवर को जुगाड़ के साथ दोबारा शुरू करवाया गया है।

पिछले दिनों विभाग के चेयरमैन को इसको नए सिरे से 8 लेन करने के लिए निर्देश दिए जिसमें रीजनल ऑफिस द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर जालंधर को संबंधित विभागों से तालमेल करने के लिए जिम्मेवारी सौंपी गयी अब यह फ्लाईओवर मौजूदा मटेरियल की महंगी कीमतों से बनेगा जिसको की अगर पहले से ही सही बना दिया जाता तो इसको दोबारा ना बनाना पड़ता और पता नहीं लोगों को कितने साल और परेशान होना पड़ेगा।

इसकी लड़ीवार में विभाग के पेट्रोलिंग अधिकारियों द्वारा विज्ञापन नीति की धज्जियां उड़ाई जा रही है जिसमें उसके द्वारा प्राइवेट हस्पतालों, रेस्टोरेंट वालों के अवैध विज्ञापन लगवाकर उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है और यही नहीं इस के साथ विभाग के मंत्री की योजनाओं को ठेंगा भी दिखाया जा रहा जिसमें वो देश में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे है ताकि की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बढ़ा कर व्यापार को बढ़ाया जा सके परन्तु विभाग के कुछ अफसरों द्वारा किसी निजी हॉस्पिटल के विज्ञापन को लगा कर डिजाइन स्पीड लिमिट 90 किलोमीटर प्रति घंटा को घटाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा करने के किसने हुक्म दिए यह सब जांच का विषय है। इस गंभीर मुद्दे पर जालंधर ब्रीज की टीम दुआरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंबाला से ई मेल के माध्यम से संपर्क साधा गया परन्तु उन्होंने ई मेल का जबाव देना जरूरी नहीं समझा उसके बाद इन सब की गंभीरता को समझते हुए उनसे फोन पर संपर्क साध कर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने संविधानिक पद पर बैठ कर गैर जिम्मेवारन ब्यान देते हुए यह कहा की हमारे पास 600 किलोमीटर की सड़कें है और इसके लिये हम दो ही अफसर है इसलिए कहाँ क्या हो रहा है।

हम नहीं देख सकते यह जिम्मेवारी ठेका प्राप्त कंपनी की है इस जवाब ने उनकी काबलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है और इस बात को हवा दी है कि कहीं ठेका प्राप्त कंपनी के साथ उनकी शामूलियत तो नहीं ? यह सब जांच का विषय है।

छाया : रवि

छाया : रवि

जालंधर ब्रीज के पिछले अंक में प्रकाशित की गयी खबर।

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges &
*Pay money after the visa

IELTS | STUDY ABROAD

*T&C apply

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

दखल

लैंगिक असमानता की चुनौतियां

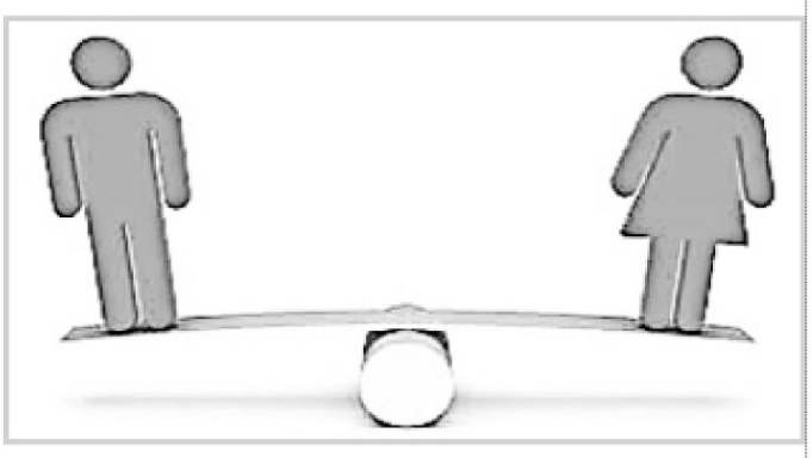

लैंगिक भेदभाव किसी के मन में यकायक उत्पन्न नहीं होता। यह समाजीकरण की उस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से ही जन्म लेता है, जो बाल्यकाल से ही आरंभ हो जाती है। महिलाओं के भीतर इस मिथ्या सोच को अंकित करने का निरंतर प्रयास किया जाता है कि महिलाओं का मूल दायित्व परिवार की देखभाल और घरेलू कार्य करना ही है। लैंगिक असमानता की खाई को पाटने के लिए भारत में निचले स्तर तक काम करना होगा। समाज के हर वर्ग तक यह बात पहुंचानी होगी कि स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव खत्म किया जाए।

विगत दशकों में कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जिन पर दुनिया भर में निरंतर चर्चा होती रही हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई सार्थक परिणाम सामने देखने को नहीं मिले। 'लैंगिक समानता' का मुद्दा भी इन्हीं में से एक है, जो तमाम कोशिश के बावजूद कायम है। लैंगिक समानता के लिए वर्ष 2020 को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष बेजिंग घोषणापत्र की 25वीं वर्षगांठ है और महिला सशक्तिकरण पर यह घोषणा पत्र अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वैश्विक मंच पर बड़ा सवाल यही है कि ऐसे कौन से कारण हैं कि तमाम प्रयासों के बाद भी लैंगिक असमानता समाप्त करने की दिशा में ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्यों में लैंगिक समानता भी शामिल है और दुनिया के 193 देशों में जिसमें भारत भी है, ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार 2030 तक हरेक देश को अपने यहां लैंगिक असमानता को समाप्त करना है।

विभिन्न अध्ययनों से यह बात सामने निकल कर आई है कि लैंगिक भेदभाव के बीज तो बालपन में ही बो दिए जाते हैं। इसमें प्रत्यक्ष भूमिका घर-परिवार और अप्रत्यक्ष भूमिका विद्यालयों की होती है। इस तथ्य की पुष्टि दो तथ्यों से होती है। पहला अध्ययन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का है, जो बताता है कि घर में बच्चे के जन्म के बाद से ही लिंग आधारित भेदभाव शुरू हो जाता है, जो न सिर्फ बच्चे को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, अपितु उसके मस्तिष्क को भी कुंद कर देता है। नतीजन बच्चा एक ही दायरे में सोचना शुरू कर देता है। वहीं, दूसरा अध्ययन 'ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2020' का है, जो यह दावा करता है कि विश्व भर में स्कूली पाठ्यक्रमों में महिला छवियों की संख्या न सिर्फ पुरुषों की तुलना में कम हैं और जिन महिलाओं की छवि दिखाई गई है, वहां इन्हें सिर्फ पारंपरिक भूमिकाओं में ही चित्रित किया गया है। विभिन्न शोध यह स्पष्ट कर चुके हैं कि लैंगिक समानता की दिशा में जारी प्रयासों को और भी विस्तारित करने के लिए जरूरी है कि महिलाओं को पेशेवर के तौर पर ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाए और पुरुषों को देखभाल करने वाले घरेलू काम करने वाले के रूप में।

मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट 'जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स' में 75 देशों में अध्ययन किया गया। इन देशों में विश्व की लगभग 80 फीसद आबादी बसती है। यह अध्ययन बताता है कि लैंगिक असमानता दूर करने के क्षेत्र में पिछले दशकों में हुई प्रगति के बावजूद अब भी 90 फीसद पुरुष एवं महिलाएं ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ किसी न किसी तरह का पूर्वाग्रह रखते हैं। इस अध्ययन से एक महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आई कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी महिलाओं को लेकर पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। यह तथ्य हैरान करने वाला तो है ही, साथ ही विचारणीय भी है कि क्यों महिलाएं स्वयं ही लैंगिक समानता के विरुद्ध खड़ी हैं। पहली नजर में जो बात समझ में आती है, वह यह है कि लैंगिक भेदभाव किसी भी व्यक्ति के मन में यकायक उत्पन्न नहीं होता। यह समाजीकरण की उस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से ही जन्म लेता है, जो बाल्यकाल से ही आरंभ हो जाती है। महिलाओं के भीतर इस मिथ्या सोच को अंकित करने का प्रयास किया जाता है कि महिलाओं का मूल दायित्व परिवार की देखभाल और घरेलू कार्य करना ही है। स्कूली पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी नकारात्मक भूमिका निभाती हैं। यह सच है कि विद्यालय का शिक्षण व्यवहार स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से कभी भी लैंगिक असमानता का समर्थन नहीं करता है, लेकिन विद्यालय में लैंगिक असमानता अदृश्य स्वरूप में पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में मौजूद है।

यह सर्वविदित है कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को आधिकारिक ज्ञान के रूप में देखा जाता है। इनमें जो ज्ञान, सूचना, भाषा आदि प्रयुक्त होते हैं, वह लैंगिक भेदभाव को उद्घाटित करते हैं। इस तथ्य की पुष्टि यूएनडीपी की 'जेंडर सोशल नॉर्मस इंडेक्स' रिपोर्ट से भी होती है। अधिकतर सभी पाठ्य पुस्तकों में लड़कों को बहादुर और तमाम विशेषणों से निरूपित किया जाता है और यही प्रतिरूप एक तरह के लैंगिक विषय-कायदे गढ़ते हैं। यही नहीं, विद्यालयों में औपचारिक एवं छद्म पाठ्यक्रम लड़कों और लड़कियों के मध्य विषयों के चयन संबंधी निर्णयों में लिंग आधारित विचारों को चुनौती देने के बजाय इसे बनाए रखने पर बल देते हैं। ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट इस बात पर ठप्पा लगाती है कि इटली, स्पेन, अमेरिका जैसे देशों में भी महिलाओं को एक रूढ़िबद्ध तरीके से ही प्रस्तुत किया जाता है। महिलाओं को निरंतर परंपरागत रूप में दिखाने की प्रवृत्ति के चलते बाल-मन में यह छवि रच बस जाती है कि महिलाओं का काम खाना बनाना है और पुरुषों का काम घर से बाहर जाकर काम करना है। फिर यही सोच पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। यह मानसिकता जितनी मजबूती से लड़कों को जकड़ती है, उतना ही प्रभाव लड़कियों के मन-मस्तिष्क पर भी पड़ता है।

यही कारण है कि परिपक्व होने पर वे स्वयं न केवल इस लैंगिक असमानता को सहजता से स्वीकार कर लेती हैं, अपितु उस विचारधारा का भी अभिभाज्य अंग बन जाती हैं, जो यह मानती है कि स्त्री, पुरुष से हर क्षेत्र में कमतर होती है। इस संपूर्ण सोच की प्रक्रिया को हम 'ब्राइट गर्ल इफेक्ट' कह सकते हैं। हम इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि चूंकि पाठ्यक्रम की पुस्तकें बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा लिखी जाती हैं, इसलिए उसमें अंकित सभी बातों को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। सदियों से पैठ बनी लैंगिक पूर्वाग्रह की सोच पर पाठ्यपुस्तकें स्वीकृति की मुहर लगा देती हैं। इसलिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि इस बिंदु पर गहराई से विचार किया जाए। यों तो पिछले वर्ष मानव संसाधन मंत्रालय ने प्ले-स्कूल के दिशा निदेर्शों में लैंगिक समानता की सिफारिश की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने कहा है कि लैंगिक रूढ़ियों को प्ले-स्कूल के स्तर पर ही खत्म किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे जब बड़े हो तो वे लिंग के आधार पर पक्षपात नहीं करें। यह भी दिशानिर्देश दिए गए कि शिक्षकों को ऐसी भाषा से बचना चाहिए, जो किसी एक लिंग या अन्य तक सीमित हो, उन्हें तटस्थ भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए।

भाषा के महत्व को कई देशों ने स्वीकार किया है। कैलिफोर्निया के बर्कले शहर में बर्कले सिटी काउंसिल ने उन शब्दों को बदलने का फैसला किया है, जिनसे स्त्री या पुरुष की भनक लगती है। इस आदेश के अनुसार 'सीवरेज तंत्र' के जो 'मैनहोल' होते हैं, उन्हें 'मेंटनेंस होल' कहा जाएगा। मैनपॉवर को 'वर्क फोर्स' या फिर 'मैन एफर्ट' कहा जाएगा। इस दिशा में स्वीडन जो कि लैंगिक समानता के मामले में पहले पायदान पर खड़ा है, ने हाल के वर्षों में लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए नए शब्द 'हेन' का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष की लैंगिक पहचान कराए बगैर उसके संबंध में बात करने या जानकारियों के आदान-प्रदान करने के लिए होता है। लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने की दिशा में निसंदेह इस तरह के प्रयास सार्थक पहल हैं, परंतु इस सोच को गति तभी मिल सकती है जब संपूर्ण भारत में इस तरह की विचारधारा स्थापित की जाए, जहां पुरुष और स्त्री के मध्य असमानता उत्पन्न करने वाली भाषाई दीवार अस्तित्व कायम ना रख सके। लैंगिक असमानता की खाई को पाटने के लिए भारत में निचले स्तर तक काम करना होगा। ■

विचार

घरेलू रक्षा उद्योग बढ़ेगा आगे

आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत केंद्र सरकार ने रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब सेना के लिए बंदूक से लेकर मिसाइल देश में बनाई जाएगी। इससे भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत अहम घोषणा की है। रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि जो 101 वस्तुएं चिन्हित की गई हैं, उनमें बड़ी बंदूकों से लेकर मिसाइल तक शामिल हैं। रक्षा मंत्री का कहना है कि इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेंगे। रक्षा मंत्री के मुताबिक, आयात पर रोक लगाने की यह कवायद 2020 से 2024 के बीच पूरी की जाएगी। आने वाले वक्त में और वस्तुओं को इस लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। घरेलू स्तर पर इन वस्तुओं के उत्पादन की समय सीमा सुनिश्चित हो, इसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस घोषणा का के गंभीर मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर चुके हैं, यह उस दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत उन देशों में शामिल हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करते हैं।

वर्ष 2015-2019 के बीच विदेशों से हथियार आयात करने के मामले में भारत का नंबर सऊदी अरब के बाद दूसरा था। दुनियाभर के कुल हथियार आयात में भारत का हिस्सा 9.2 फीसदी है। इससे अंदाजा लगाइए कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर कितना निर्भर है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए यह फैसला किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने जिन 101 उत्पादों की लिस्ट जारी की, उनमें सामान्य उपकरणों से लेकर हाई-एंड इक्विपमेंट्स तक शामिल हैं। इस लिस्ट का मकसद भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को यह जताना है कि सेनाओं को किन-किन चीजों की जरूरत है ताकि वह खुद को इसके लिए तैयार कर सकें। रक्षा मंत्रालय ने अगले 6-7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके देने की योजना बनाई है। यह लिस्ट अचानक ही तैयार नहीं हुई, इसके पीछे कई दौर की बातचीत है।

सेना, नौसेना, वायुसेना के अलावा डीआरडीओ, डिफेंस पीएसयू, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और प्राइवेट इंडस्ट्री से भी कंसल्ट किया गया है। यानी पूरी तैयारी के बाद ही यह कदम उठाया गया है। देश में किन आर्म्स, इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स का प्रोडक्शन तेजी से हो सकता है, इसकी जानकारी करने के बाद ही लिस्ट बनाई गई है ताकि फैसले से भारत की रक्षा क्षमता प्रभावित न हो। डिफेंस सेक्टर को लेकर दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता तो कम होगी ही, इस फैसले से डिफेंस इंडस्ट्री में नई जान फूंकी जा सकती है। सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों से महंगे दाम पर सामान नहीं मंगाना पड़ेगा, साथ ही तकनीकी सुरक्षा की चिंता भी कम होगी। भारत की तकनीकी दक्षता में इजाफे के साथ-साथ अगर हमारी जरूरतें पूरी होती हैं तो हम एक्सपोर्ट की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अब केंद्र सरकार के ताजा फैसले से रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट इंडस्ट्री को भी उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अंतरिक्ष में जंग का बढ़ता खतरा

आज से 12 साल पहले साल 2008 में अमेरिका ने अंतरिक्ष से बेकाबू होकर गिर रहे जासूसी उपग्रह को एक इंटरसेप्टर मिसाइल से मार गिराया, तो दुनिया में बड़ी सनसनी फैल गई थी। अमेरिका का कहना था कि धरती की तरफ बढ़ते उस उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट करना ही इकलौता उपाय था। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह अनियंत्रित होकर आबादी वाले किसी हिस्से में गिर सकता था। ऐसा होने पर उपग्रह में मौजूद खतरनाक किस्म का ईंधन- हाइड्राजीन भारी मुसीबत बन जाता, क्योंकि उसकी चपेट में आने वाले इंसान और जानवरों के फेफड़े, त्वचा और बालों को नुकसान हो सकता था। लेकिन तब अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी रूस ने अमेरिकी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। रूस ने कहा कि उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट करना तो बहाना भर था। असल में अमेरिका तो अंतरिक्ष युद्ध की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना पर अमल करते हुए अपने अंतरिक्षीय हथियारों का परीक्षण करना चाहता था। एक चिंता यह भी पैदा हुई थी कि अंतरिक्ष में उपग्रहों को मार गिराने से वहां कचरे की समस्या और बढ़ जाएगी।

ये दोनों आशंकाएं पूरी ताकत से एक बार फिर मानव समुदाय के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। हालांकि इस बार ऐसी गतिविधि का आरोप अमेरिका ने रूस पर मढ़ा है। मामला बीते साल नवंबर में अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित रूस के उपग्रह कॉस्मॉस-2542 का है, जिसे लेकर अमेरिका ने एक के बाद एक कई गंभीर खुलासे किए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूसी जासूसी उपग्रह से मध्य जुलाई-2020 में मिसाइल जैसी कोई चीज निकली, जो एक अन्य रूसी उपग्रह के पास से होकर गुजर गई। अमेरिका ने इस चीज को एक उपग्रह भेदी मिसाइल बताया। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि इस तरह रूस अंतरिक्ष का सैन्यीकरण कर रहा है। यानी बाजी पलट गई है। जैसे आरोप पहले अमेरिका पर रूस लगाता था, अब कुछ वैसा ही भय अमेरिका रूस की तरफ से महसूस कर रहा है।

सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन के अंतरिक्ष निदेशालय ने भी बयान जारी कर कहा कि रूस ने हथियार जैसी किसी चीज को प्रक्षेपित कर अपने एक उपग्रह का परीक्षण किया है, उसे लेकर हम चिंतित हैं क्योंकि इस तरह की कार्रवाई अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए खतरा है। अमेरिका और ब्रिटेन, दोनों का कहना है कि यह उपग्रह को मार गिराने वाली मिसाइल थी, जिसका रूस ने परीक्षण किया है। इस पूरे मामले पर रूस की सफाई भी आई है। उसके रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि 15 जुलाई को जो परीक्षण किए गए थे, उनसे किसी भी दूसरे अंतरिक्ष यान के लिए कोई खतरा पैदा नहीं हुआ

अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं लगता, जब ताकतवर मुल्क अंतरिक्ष में भेजे जा रहे अपने उपग्रहों को सिर्फ जासूसी के काम में नहीं लगाएंगे, बल्कि मिसाइलों से लैस कर उन्हें लड़ाकू भूमिका में भी ला सकते हैं और सिर्फ एक बटन दबा कर धरती पर बैठे-बैठे अंतरिक्ष में तबाही ला सकते हैं। हालांकि, इस मामले में भारत भी पिछले साल पूरी दुनिया को ताकत दिखा चुका है, लेकिन यह जंग किसी के काम की नहीं है।

और न ही इसने किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। रूस का कहना है कि यह उपग्रह भेदी मिसाइल नहीं, बल्कि उपग्रह कॉस्मॉस-2542 के अंदर से निकला एक अन्य छोटा उपग्रह है। उल्लेखनीय है कि इसी साल फरवरी में इस उपग्रह पर नजर रख रहे अमेरिका ने दावा किया था कि कॉस्मॉस-2542 से एक नया उपग्रह कॉस्मॉस-2543 निकला था और ये दोनों उपग्रह तब से करीब सौ मील की दूरी पर रहते हुए एक अमेरिकी जासूसी उपग्रह की निगहबानी कर रहे हैं।

जितना हैरतअंगेज मामला उपग्रह के अंदर से नया उपग्रह निकालने वाला था, उतना ही आश्चर्यजनक यह भी है कि कोई उपग्रह अंतरिक्ष में रहते हुए अपने भीतर से मिसाइल छोड़े और किसी अन्य उपग्रह पर हमला कर दे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि कॉस्मॉस-2542 से निकली चीज मिसाइल ही थी। लेकिन मामले को देखते हुए अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं लगता, जब ताकतवर मुल्क अंतरिक्ष में भेजे जा रहे अपने उपग्रहों को सिर्फ जासूसी के काम में नहीं लगाएंगे, बल्कि मिसाइलों से लैस कर उन्हें लड़ाकू भूमिका में भी ला सकते हैं और सिर्फ एक बटन दबा कर धरती पर बैठे-बैठे अंतरिक्ष में तबाही ला सकते हैं। अब तक दुनिया के चार देश- अमेरिका, रूस, चीन और भारत अंतरिक्ष में उपग्रह भेदी मिसाइल तकनीक को लेकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर चुके हैं। भारत ने 2019 में 'मिशन शक्ति' के तहत अंतरिक्ष में तीन सौ किलोमीटर दूरी पर स्थित लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) सैटेलाइट को मार गिराया था। यह एक मौसम उपग्रह था।

रक्षा वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह भारत ने अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ने की आशंकाओं के मद्देनजर प्रतिरोधक शक्ति हासिल कर ली है। यदि कोई देश उपग्रहों को निशाना बनाएगा, तो भारत अंतरिक्ष में जवाबी कार्रवाई कर सकता है। पड़ोसी चीन ने तो 2007 में अंतरिक्ष में 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित उपग्रह को नष्ट कर यह ताकत हासिल कर ली थी। मूल प्रश्न यही है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ऐसे युद्ध की आशंका कितनी ज्यादा है। महाशक्ति देश अमेरिका तो हमेशा ही इस मामले में बादशाहत कायम करना चाहता है। इसका सपना सबसे पहले साल 1983 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने देखा था। वे चाहते थे कि पृथ्वी पर जो युद्ध होते हैं, उन पर अंतरिक्ष में तैनात सैनिक उपग्रहों और उपकरणों से इस तरह नियंत्रण पाया जाए कि अमेरिका और उसके मित्र देश हमेशा बढ़त पा सकें। हालांकि तमाम कारणों से 13 साल तक योजनाओं पर अमेरिका अमल नहीं कर सका।

1996 में बिल क्लिंटन के सत्ता में आते ही इस पर नए सिरे से सुगबुगाहट शुरू हो गई। लेकिन इस पर होने वाले खर्च और अंतरिक्ष की शांति के मद्देनजर क्लिंटन प्रशासन ने योजना को ठंडे बस्ते में डालना उचित समझा। हालांकि जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप अलग ही सोच के निकले। 2008 में बुश प्रशासन ने अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती पर एक रिपोर्ट में कहा था कि इससे न सिर्फ अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता है, बल्कि दूसरे देशों को अंतरिक्ष में बढ़त लेने से रोक सकता है। ट्रंप प्रशासन को महसूस हुआ कि रूस-चीन की इस मामले में बढ़त को देखते हुए जरूरी है कि स्टार वॉर की योजनाओं को झाड़-पोंछ कर फिर से देखा जाए और अंतरिक्ष से क्या युद्ध हो सकते हैं- इसकी संभावनाएं टटोली जाएं। इस बाबत मार्च-2018 में अमेरिकी रक्षा खुफिया के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट पी. एश्ले जूनियर ने अमेरिकी सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने बयान दिया था कि रूस और चीन ऐसे हथियार विकसित कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल वे अंतरिक्ष में जंग में कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अमेरिका तैयारियों के बारे में पुनर्विचार करे।

वैसे तो अभी तक इस तकनीक से संपन्न सभी देश यह दावा कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में हथियारों के परीक्षण का मकसद सुरक्षा को पुख्ता करना है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था अब अंतरिक्ष में तैनात कामकाजी उपग्रहों पर टिकी है। ये उपग्रह मौसम पर नजर रखते हैं, इंटरनेट से लेकर दूरसंचार के तमाम कार्यों को संपन्न कराते हैं, दुश्मन देशों की गतिविधियों की निगरानी करते हैं और पृथ्वी के अन्वेषण का काम करते हैं, जिनसे जरूरी डाटा मिलता है और देश के विकास में मदद मिलती है। ऐसे में यदि कोई देश किसी मुल्क को ठप करना चाहे तो उसके उपग्रहों को निशाना बना कर कर सकता है और धरती पर वास्तविक जंग किए बगैर भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में यदि उपग्रहों पर निर्भर देश अंतरिक्ष में तैनात अपने उपग्रहों की सुरक्षा के उपाय के तौर पर भी उपग्रह रोधी मिसाइलों का परीक्षण करता है, तो उससे भी अंतरिक्ष की जंग का खतरा पैदा होता है। अंतरिक्ष में बढ़ता जंग का खतरा पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा कर सकता है। लिहाजा, हथियारों की दौड़ को जमीन पर ही रहने देना चाहिए। ■

ट्विटर

रक्षा क्षेत्र में भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब हम आयात से ध्यान हटाएंगे और सेना की जरूरतें खुद पूरी करेंगे, तो असर दिखेगा।

कमर आगा, रक्षा विशेषज्ञ

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उठाया गया सरकार का कदम सराहनीय है। इसे बेहतर प्लानिंग के साथ लागू करना होगा ताकि विवाद की गुंजाइश न रहे।

मारुफ रजा, रक्षा विशेषज्ञ

सत्यार्थ

जैसी सोच, वैसा जीवन

एक बार किसी कस्बे में एक महात्माजी पधारे। लोगों ने उनसे प्रवचन देने का आग्रह किया, तो महात्माजी ने कहा- मैं क्या बोलूं, आप तो सब जानते हैं। जो अच्छा है, उसे करो तो जो बुरा है, उसे मत करो, उसे त्याग दो। महात्माजी की इस बात पर वहां मौजूद लोगों में से एक ने कहा- महाराज, हम सब बहुत अच्छे बनना चाहते हैं और इसके लिए यथासंभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे अच्छे तो दूर, अच्छे भी क्यों नहीं बन पाते? तब महात्माजी ने कहा-हम अपने ऊपर जैसी मोहर लगाते हैं, वैसा ही तो बनेंगे। उनकी यह बात लोगों की समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की- महात्मन् इसे स्पष्ट करें। तब उन्होंने अपनी जेब से तीन नोट निकाले और उनसे पूछा-ये कितने-कितने के नोट हैं? एक नोट दस रुपए का था, दूसरा सौ रुपए का और तीसरा हजार का। इसके बाद महात्माजी ने पूछा- इनमें क्या अंतर है? अब लोग चुप थे। महात्माजी ने समझाया- ये तीनों नोट एक जैसे कागज पर छपे हैं। कागज के पहले टुकड़े से दस रुपए की चीज खरीदी जा सकती है, तो दूसरे से सौ रुपए की और तीसरे से हजार की। यह कागज पर लगी मोहर या छाप के द्वारा निर्धारित हुआ है। हमारा जीवन भी एक कोरे कागज की तरह ही है। हम चाहें तो उस पर दस रुपए के बराबर छोटी-मोटी विशेषता या गुण की मोहर लगा सकते हैं और चाहें तो हजार रुपए या उससे भी अधिक की कीमत के गुणों की मोहर लगा सकते हैं। जैसी छाप या सोच, वैसा जीवन। इस संसार रूपी छापेखाने में मन रूपी कागज पर केवल सात्विक और जीवनोपयोगी उच्च विचारों की मोहर लगाकर ही अपने जीवन को हर प्रकार की उत्कृष्टता प्रदान की जा सकती है।

■ आशा गुप्ता

स्वतंत्रता दिवस की तैयारी

देशभर में कोरोना संक्रमण के बीच स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान ठाणे में एक दुकान पर बच्चों को त्रिरंगे मॉस्क प्रभावित कर रहे हैं और वे इन्हें उत्साह के साथ खरीद रहे हैं।

ताइवान में घुसे चीनी लड़ाकू विमान मिसाइलों को पीछे आते देख भागे

अमेरिका पर खीझ निकालने की कोशिश पड़ी भारी

ताइपे, (एजेंसी)। अमेरिका और चीन के लिए जंग का मैदान बन चुके ताइवान में एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा (एचएचएस) मंत्री एलेक्स अजार के नेतृत्व में रविवार को शीर्ष अमेरिकी दल के ताइवान पहुंचने से चिढ़े चीन ने सोमवार सुबह लड़ाकू विमानों के लिए घुसपैठ की, जिसका करारा जवाब दिया गया। ताइवान स्ट्रेट मिड-लाइन को जैसे ही चीनी विमानों ने पार किया, ताइवान ने मिसाइलों को दाग दिया और पेट्रोलिंग विमान भी पीछे लगा दिए। इसके बाद चीनी विमान झटपट वहां से निकल गए।

चार दशक बाद अमेरिका से इस स्तर का कोई आधिकारिक दल ताइवान पहुंचा है, जिसकी चीन ने निंदा की है। चीन ताइवान पर अपना हक जताता रहा है। सोमवार को अजार के ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात से कुछ देर पहले स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे चीन के जे-11 और जे-10 विमानों के साथ घुसपैठ की।

ताइवान की समर्थन करने यहां पहुंचे यूएस के मंत्री अजार

अजार ताइवान के साथ आर्थिक और स्वास्थ्य सहयोग मजबूत करने और कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई में ताइवान की भूमिका का समर्थन करने के लिए यहां पहुंचे हैं। अजार ने साई से कहा कि कोविड-19 के खिलाफ ताइवान का रेस्पॉन्स दुनिया के सबसे सफल तरीकों में है। गौरतलब है कि चीन के बेहद करीब होने के बावजूद ताइवान में महज 480 लोग संक्रमित हुए और सात लोगों की ही जान गई।

ताइवान ने चीनी विमानों को सीमा से बाहर खदेड़ा

ताइवान रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में एयर फोर्स ने कहा कि चाइनीज विमानों का जमीन से मार करने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से पीछा किया गया। पेट्रोलिंग कर रहे ताइवानी लड़ाकू विमानों ने भी चीनी विमानों को सीमा से बाहर खदेड़ दिया। 2016 के बाद यह तीसरा मौका है जब चीनी लड़ाकू विमानों ने इस रेखा को पार किया।

लोकतांत्रिक आइलैंड को अमेरिका का मजबूत समर्थन

बीजिंग से बेहद खराब रिश्तों के बीच ट्रंप प्रशासन ने लोकतांत्रिक आइलैंड को मजबूत समर्थन को प्राथमिकता पर रखा है और हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है। अजार ने साई से मुलाकात के दौरान कहा कि ताइवान के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दोस्ती और समर्थन के संदेश को लेकर यहां होना वाकई सम्मान की बात है। गौरतलब है कि बीजिंग के समर्थन में 1979 में वॉशिंगटन ने ताइपे के साथ आधिकारिक रिश्ता खत्म कर लिया था।

न्यूज

पेटीमुडी भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 49

इडुक्की, (एजेंसी)। केरल के इडुक्की जिले में पेटीमुडी के पास राजामलाई के चाय बागान में हुए भूस्खलन में छह और शव मिलने से सोमवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई। भारी बारिश के बावजूद लापता लोगों की खोज जारी है। सभी शव घटनास्थल के पास की नदी में पाए गए है और उनकी पहचान नहीं हो सकी है। दमकल सेवा के स्कूबा गोताखोरों ने नदी से शवों को निकाला। ऐसा माना जा रहा है कि ये सभी कीचड़ के साथ नदी में बह गए। रिपोर्टों के अनुसार बचाव दल ने मनकुलम क्षेत्र के पास नदी में खोज करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि छह अगस्त को राजामलाई-पेटीमुडी में हुई भूस्खलन की इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है।

धमाकों के बाद, लेबनान में पूरी सरकार का इस्तीफा

बेरुत, (एजेंसी)। लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले सप्ताह हुए धमाके को लेकर प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार ने ही इस्तीफा दे दिया है। बेरुत धमाके के बाद सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था, उसी को लेकर पूरी सरकार ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री हसन दिआब जल्द ही इसकी घोषणा करने वाले हैं। इस्तीफा देने के बीच देश के एक न्यायाधीश ने सोमवार को सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों से पूछताछ शुरू की। सरकारी 'नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार न्यायाधीश गस्सान एल खोरी ने सुरक्षा प्रमुख मेजर जनरल टोनी सलीबा से पूछताछ शुरू की। इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है और अन्य जनरलों से भी पूछताछ होनी है। गौरतलब है कि गत चार अगस्त को हुए विस्फोट में 160 लोगों की मौत हुई थी और लगभग छह हजार लोग घायल हुए थे।

पिता-पुत्र हिरासती मौत मामले में आरोपी ASI की मौत

मदुरै, (एजेंसी)। तमिलनाडु में पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत मामले में गिरफ्तार पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) पौलदुरई (56) की कोरोना संक्रमित होने के बाद यहां गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पिटल (जीआरएच) में सोमवार को मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पौलदुरई 24 जुलाई को मदुरै सेंट्रल जेल में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। पौलदुरई हिरासत में पिता-पुत्र की मौत मामले में जेल में बंद थे। पौलदुरई को 24 जुलाई को संक्रमित पाए जाने के बाद जीआरएच में भर्ती कराया गया, जहां अच्छी इलाज के बावजूद सोमवार को सुबह उनकी मौत हो गई। वह तुतुकुडी में पुलिस हिरासत में पी जयराज और उनके पुत्र जे बेनिक्स की हुई मौत मामले में आरोपी 10 पुलिस कर्मियों में शामिल थे।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे!
कोरोना वायरस से सावधान रहे क्योंकि सावधानी ही बचाव हैं। कोरोना को धोना हैं।

खाड़ी सहयोग परिषद ने की संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध आगे बढ़ाने की वकालत

ईरान को घेरने के लिए एक साथ आए छह खाड़ी देश

दुबई, (एजेंसी)। सऊदी अरब समेत खाड़ी के छह देशों के एक समूह ने अपने आंतरिक कलहों को दरकिनार करते हुए रविवार को ईरान पर हथियारों को लेकर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वकालत की। ईरान पर लगा मौजूदा प्रतिबंध दो महीने में समाप्त होने वाला है। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) ने कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजा है, जिसमें ईरान पर प्रतिबंध बरकरार रखने का समर्थन किया गया है।

इस प्रतिबंध की वजह से ईरान विदेश में निर्मित युद्धक विमान, टैंक और हथियार नहीं खरीद सकता है। खाड़ी सहयोग परिषद में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। परिषद का आरोप है कि ईरान ने पड़ोसी देशों में सीधे या संगठनों और गतिविधियों के माध्यम से हथियारों के जरिए दखल देना बंद नहीं किया है। इनका कहना है कि ऐसे संगठन ईरान की ओर से प्रशिक्षित किए गए होते हैं।

यमन में हूती विद्रोहियों के साथ युद्ध जारी

सऊदी नीत गठबंधन का यमन में हूती विद्रोहियों के साथ युद्ध जारी है। हूती विद्रोहियों के बारे में सयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और हथियार विशेषज्ञों का आरोप है कि इन्हें हथियारों की आपूर्ति ईरान द्वारा की जाती है। हालांकि ईरान हूतियों को हथियार और जरूरी चीजें मुहैया कराने से इंकार करता रहा है लेकिन लगातार ईरान के हथियार यमन में मिलते हैं।

जीसीसी पर भड़का ईरान, बयान की निंदा की

जीसीसी का कहना है कि जब तक ईरान इस क्षेत्र को अस्थिर करने वाली अपनी गतिविधियों और आतंकवादियों और विभाजनकारी संगठनों को हथियार की आपूर्ति कराने वाली गतिविधियों को नहीं छोड़ता है, तब तक उस पर से प्रतिबंध हटाना अनुचित होगा। ईरान के सरकारी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास मूसावी ने जीसीसी के इस पत्र की निंदा की है और उसे 'गैरजिम्मेदाराना' बयान करार दिया है। मूसावी ने खाड़ी अरब देशों की आलोचना करते हुए कहा कि ये देश दुनियाभर में और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हथियारों की खरीद करने वाले देश हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनावों के बीच उस पर 2010 में विदेशों से हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले से खाड़ी में तनाव और बढ़ गया है।

बिहार में बाढ़ : मुजफ्फरपुर-दरभंगा में तबाही

बूढ़ी गंडक और बागमती अब भी खतरे के निशान के ऊपर

मुजफ्फरपुर, (एजेंसी)। उत्तर बिहार में दो नदियों से तबाही अब भी जारी है। बूढ़ी गंडक एवं बागमती में पानी घटने के बावजूद जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। मुजफ्फरपुर व दरभंगा में इन दोनों ने तबाही मचा रखी है। बांध एवं एनएच पर शरण लेने वाले हजारों लोग घर लौटने की ताक में हैं, लेकिन नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने से इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही।

मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर अब भी 52.86 मीटर पर बना हुआ है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं बागमती का भी जलस्तर 54.80 मीटर है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। दोनों नदियों ने जिले में तबाही मचा रखी है। जिले में बाढ़ से 14 प्रखंड के 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बूढ़ी गंडक के पानी से तिरहुत नहर टूटने के बाद सकरा एवं मुरौल के सैकड़ों लोगों ने एनएच 28 पर शरण ले रखी है। यहां प्रभावित गांव में पानी कम हो रहा है।

पाकिस्तान के चमन शहर में ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत, कई घायल

क्वेटा, (एजेंसी)। पाकिस्तान के चमन शहर में सोमवार को एक निमार्णाधीन इमारत के पास एक जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें कम से कम पांच लोग मारे गए हैं और 10 अन्य घायल हो गए। इसकी जानकारी पुलिस ने दी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में कानून प्रवर्तन एजेंसियों का हवाला देते हुए कहा इंप्रूवाइज्ड इक्सप्लोजिव डिवाइस (आईईडी) को शहर के माल रोड इलाके में एक मोटरसाइकिल पर लगाया गया था।

विस्फोट इतना तेज था कि पास के एक मैकेनिक की दुकान में आग लगने से दुकान पूरी तरह से नष्ट हो गई। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, जबकि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है।

आगरा में बिगड़ी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तबीयत

आगरा ■ एजेंसी

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की तबीयत सोमवार दोपहर अचानक खराब हो गई। इस दौरान डिप्टी सीएम आगरा में कोविड-19 की समीक्षा बैठक ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान उनकी नाक से खून निकला है। डिप्टी सीएम की तबीयत बिगड़ते ही आनन-फानन में मेडिकल टीम बुलाई गई।

बता दें कि ये बैठक आगरा के सर्किट हाउस में चल रही थी। बताया जा रहा है कि चेकअप के बाद वो मथुरा निकल गए। दिनेश शर्मा सोमवार सुबह ही आगरा में कोरोना संक्रमण तथा विकास कार्य की समीक्षा करने पहुंचे थे। आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को जिले में कोरोना के 38 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 2103 पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना से मरने वालों की संख्या 101 हो गई है। आगरा में एक्टिव केस अभी 308 है। कोरोना काल में शहर में अब तक 66,275 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। यहां ठीक होने वाले लोगों की दर 80.55प्रतिशत है।

नेपाली प्रधानमंत्री ओली अब भारत से दोस्ती को बेताब

काठमांडू, (एजेंसी)। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अकड़ ढीली पड़ती जा रही है। भारत के सीमा विवाद पर सख्त रवैया अपनाने के बाद अब नेपाल सरकार विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है कि किस तरह से भारत को बातचीत के लिए राजी किया जा सके।

यही नहीं, ओली भाजपा और आरएसएस के जरिए मोदी सरकार को मनाने में जुटे हुए हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवली ने कई पूर्व मंत्रियों, राजनयिकों और विशेषज्ञों से भारत को वार्ता की मेज पर लाने के लिए सलाह ली है। नेपाली विदेश मंत्री ज्ञवली ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ बातचीत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ज्ञवली ने कहा कि काठमांडू और नई दिल्ली में भारत के साथ बातचीत शुरू करने के लिए प्रयास जारी हैं, लेकिन इसके परिणाम के आने में अभी और समय लगेगा। नेपाली विदेश मंत्री के तमाम प्रयासों के बाद भी अभी यह फैसला नहीं हो पाया है कि किस तरह से भारत के साथ बातचीत की दिशा में आगे बढ़ना है।

सोना तस्करी मामला

एनआईए कोर्ट ने खारिज की स्वप्ना की जमानत याचिका

कोच्चि, (एजेंसी)। एनआईए की विशेष अदालत ने केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने एनआईए द्वारा पेश किए गए सबूतों पर गौर करते हुए स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि, पिछले साल नवंबर से राजनयिक चैनल के जरिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की सोने की तस्करी में महिला की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी ने ये सबूत जुटाए थे। एनआईए ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि मामले में गहन जांच की जरूरत है। एनआईए ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सबूत हैं कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया, जो सीधे तौर पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन है।

स्वप्ना सुरेश ने अपनी याचिका में लगाया आरोप

स्वप्ना सुरेश ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसे बिना किसी आधार के सिर्फ कल्पना के सहारे इस अपराध में फंसाया गया है और और यह मामला राज्य तथा केंद्र सरकारों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का है, जिसे मीडिया ने तूल दिया।

हथिनी के हत्यारों को ऐसी सजा मिलेगी जो मिसाल बनेगी : बाबुल

नई दिल्ली, एजेंसी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या के मामले में दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी, जो मिसाल बनेगी और और लोग दोबारा इस तरह का निर्मम कृत्य करने से डरेंगे।

केंद्रीय पर्यावरए मंत्री श्री सुप्रियो ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि केरल की घटना अमानवीय एवं जघन्य अपराध है। इस मामले में केंद्र सरकार की नीति 'जीरो टॉलरेंस' की है। दोषियों को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, किंतु मुझे उम्मीद है कि जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी, जो मिसाल बनेगी।

रूस ने अमेरिका नहीं चीन को दी है परमाणु हमले की चेतावनी

मॉस्को, (एजेंसी)। चीन अपने सभी पड़ोसियों से पंगे ले रहा है और रूस के साथ भी उसका टकराव बढ़ रहा है। इस बीच मॉस्को ने कहा है कि वह अपनी जमीन पर किसी मिसाइल हमले को परमाणु हमले की तरह लेगा और इसका जवाब परमाणु हथियारों से देगा। कुछ लोग मानते हैं कि मॉस्को ने यह चेतावनी अमेरिका को दी है, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट इसे चीन के खिलाफ साधा गया निशाना बता रहे हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं यह प्रतिक्रिया चीन द्वारा रूस के प्रभाव को क्षीण करने का परिणाम है। बीजिंग उन्नति ने रूस को चिढ़ाया है। हाल के घटनाक्रमों ने इसी ओर इशारा किया है। साथ ही चीन ने आर्कटिक और मध्य एशिया में रूस के प्रभाव को नजरअंदाज किया है और रूस के फार ईस्ट क्षेत्र में दावा किया है। रूस ने चीन पर इसके डिफेंस डिजाइन को कॉपी करने का भी आरोप लगाया है। दोनों देश अमेरिका के खिलाफ कभी-कभी साथ आ जाते हैं। मॉस्को ने बीजिंग को एस-400 सरफेस टु एयर मिसाइल सिस्टम की डिलिवरी को टाल दी। यह कदम इसलिए अहम है, क्योंकि यह ऐसे समय पर उठाया गया जब चीन साउथ चाइना सी पर दावे सहित कई मुद्दों पर घिरा हुआ है।

सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया चेन्नई-पोर्ट ब्लेयर के बीच ओएफसी का उद्घाटन

अंडमान-निकोबार में बेहतर होगी इंटरनेट स्पीड

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन अंडमान-निकोबार के दर्जनों द्वीपों में बसे लाखों साथियों के लिए तो अहम है ही, पूरे देश के लिए भी महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस को नमन करते हुए, करीब डेढ़ वर्ष पहले मुझे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना के शुभारंभ का अवसर मिला था। मुझे खुशी है कि अब इसका काम पूरा हुआ है और आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। उन्होंने कहा कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक, अंडमान-निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है। समंदर के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना, अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है।

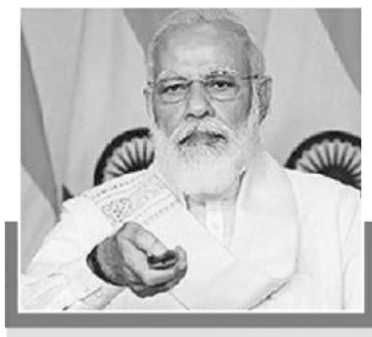

अंडमान-निकोबार के लोगों को कनेक्टिविटी के लिए बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंडमान-निकोबार के लोगों को अनंत अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि अब अंडमान-निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी, जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारत अग्रणी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा समर्पण रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर एरिया और समुद्री सीमा से जुड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास हो। अंडमान-निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट, ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

पोर्ट लेड डेवलपमेंट के हब के रूप में विकसित होने वाला है अंडमान निकोबार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार, पोर्ट लेड डेवलपमेंट के हब के रूप में विकसित होने वाला है। अंडमान-निकोबार दुनिया के कई पोर्टस से बहुत कॉम्पिटिटिव डिस्टेंस पर स्थित है। उन्होंने कहा कि अंडमान और निकोबार के 12 आइलैंड्स में हाई इंपैक्ट प्रोजेक्टस का विस्तार किया जा रहा है। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो आज हो चुका है। इसके अलावा रोड, एयर और वॉटर के जरिए फिजिकल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है।

53 वर्ष की उम्र में झारखंड के शिक्षा मंत्री ने 11वीं कक्षा में लिया प्रवेश

रांची, (एजेंसी)। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो 53 साल की उम्र में फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। उन्होंने सोमवार बोकारो के नावाडीह के देवी महतो इंटर कॉलेज की 11वीं क्लास में एडमिशन लिया है। 1995 में मैट्रिक करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। शिक्षा मंत्री बनने के बाद लोग अक्सर यह मुद्दा उठाते थे कि 10दसवीं पास व्यक्ति कैसे शिक्षा मंत्रालय संभालेगा।

क्लास के साथ संभालेंगे शिक्षा मंत्रालय : कॉलेज प्राचार्य दिनेश प्रसाद वर्णवाल ने खुद शिक्षा मंत्री का आर्ट्स संकाय में पंजीयन किया। कॉलेज के कार्यालय कक्ष में जाकर मंत्री महतो ने नामांकन फॉर्म भरा एवं 1100 रुपए शुल्क के साथ जमा करवाया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह सारा काम देखते हुए सब कुछ करेंगे। 'क्लास भी करेंगे और मंत्रालय भी संभालेंगे। घर में किसानी का काम भी करेंगे, ताकि मेरा काम देखकर लोग भी प्रेरित हों।

क्यों लिया जगरनाथ ने इंटर की पढ़ाई करने का फैसला? इसी साल जनवरी में उन्होंने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला। तभी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि 10 वीं पास को शिक्षा विभाग दे दिया है। इसके बाद ही उन्होंने तय किया था कि वे आगे की पढ़ाई करेंगे। महतो ने कहा कि शिक्षा हासिल करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। नौकरियों करते हुए लोग आईएएस, आईपीएस की तैयारी करते हैं और सफल भी होते हैं।

पंजाब राज्य पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी महासंघ ने शक्ति सदन जालंधर के बाहर की गेट रैली

■ जालंधर ब्रीज ब्यूरो

छाया : रवि

पंजाब राज्य पावर कारपोरेशन लिमिटेड और पंजाब राज्य ट्रांस्मिसन कारपोरेशन लिम्टिड पटियाला के फैसले अनुसार कर्मचारी महासंघ ने पंजाब के सभी कर्मचारियों की तरफ से पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी निति के कारण शक्ति सदन जालंधर के बाहर की गई गेट रैली। जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा जो पिछले महीनो का मोबाइल भत्ता,कर्मचारियों से किये हुए वादों से मुकर जाना,पंजाब सरकार द्वारा छठे पे कमीशन को लागु करने में देरी करना और जो महंगाई भत्ता अभी तक जारी नहीं किया गया जिससे साफ पता चलता है की पंजाब सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के भत्तों को काटने की बजाए कर्मचारियों के हकों को काटा जा रहा है । कर्मचारी महासंघ के प्रधान राकेश कुमार शर्मा ने मांग की कर्मचारियों के महंगाई भत्ते,मोबाइल भत्ते जल्द दिए जाये और छेवे पे कमीशन को लागू किया जाए। इस रैली में कर्मचारी महासंघ के प्रधान राकेश कुमार शर्मा , हरलीन सिंह सीनियर मीत प्रधान अरविंदर सिंह प्रैस सचिव, बलबीर सिंह मेंबर, जरनैल सिंह, मुकेश कुमार, संजय कुमार, प्रमोद कुमार देवी पार्षद, सुरिंदर कुमार, परमजीत कुमार आदि अन्य मौजूद थे।

जिला प्रशासन व पुलिस विभाग, लेबर विभाग, हेल्थ विभाग की मुस्तैदी से जे.के. इंडस्ट्रीज वरियाणा से छुड़वाए काम कर रहे छोटे बच्चे

छाया : रवि

■ जालंधर ब्रीज ब्यूरो

जे.के.इंडस्ट्रीज वरियाणा में जालंधर कमिश्नर पुलिस और लेबर विभाग ने छोटे बच्चों को जो वहां काम कर रहे थे उनको छुड़वाया। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने बताया की बच्चो से फैक्ट्री मालिकों द्वारा चाइल्ड लेबर एक्ट के खिलाफ काम करवाया जा रहा था पुलिस विभाग अब इसके अलग- अलग एंगल से जाँच कर रही है और इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जोड़ा जा रहा है । पुलिस सब बच्चों को अब जूवेनियल हाउस में भेजी गई और मालिकों के खिलाफ सख्त कारवाई करेगी।

SPORTS PLANET

आई.पी.एल. 2020 के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर चर्चा में पतंजलि का नाम

स्पोर्ट्स प्लैनट

कोरोना पॉजिटिव भारतीय हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह की तबीयत बिगड़ी, अस्ताल में भर्ती

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए भारतीय हॉकी टीम के फारवर्ड मनदीप सिंह को खून में आक्सीजन का स्तर गिरने के बाद बेंगलुरू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बीस अगस्त से शुरू हो रहे राष्ट्रीय शिविर के लिए बेंगलुरू पहुंचने पर मनदीप और पांच अन्य भारतीय खिलाड़ियों को पिछले हफ्ते कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। इन पांच खिलाड़ियों में कप्तान मनप्रीत सिंह, डिफेंडर सुरेंदर कुमार और जसकरण सिंह, ड्रैगफ्लिकर वरूण कुमार और गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक शामिल हैं। साइ ने बयान में कहा, ''10 अगस्त (सोमवार) की रात को जांच के दौरान पता चला कि मनदीप सिंह के खून में आक्सीजन का स्तर सामान्य से कम है जो इस बात का संकेत है कि वह कोविड के मामूली स्तर से औसत स्तर की ओर बढ़ रहे हैं।'' बयान के अनुसार, ''परिसर में मौजूद साइ अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एहतियाती कदम के तौर पर उन्हें एसएस स्पर्श मल्टीस्पेशियेलिटी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।'' पच्चीस साल के मनदीप ने भारत के लिए अब तक 129 मैचों में 60 गोल दागे हैं। वह 2018 में एशियाई चैंपियन्स ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। साइ के अनुसार एक महीने के ब्रेक के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से बेंगलुरू पहुंचने के दौरान खिलाड़ी इस संक्रमण का शिकार हुए। साइ ने बताया कि खिलाड़ियों की दिन में चार बार जांच की जा रही है। भारत में अब तक इस वायरस से 22 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं जबकि 45 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है।

पंजाब में कोविड केस बढ़ने पर कैप्टन द्वारा प्रधानमंत्री को उदारता से वित्तीय पैकेज देने की मांग

प्रधानमंत्री को एस.डी.आर.एफ. में से कोविड से संबधित खर्च करने की शर्तें नरम करने के लिए कहा

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब में कोविड मामलों में विस्तार होने और पहली तिमाही में 50 प्रतिशत राजस्व गिरावट के मद्देनज़र पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से महामारी से राजस्व की वसूली के पड़े फर्क को पूर्ण करने के लिए राज्यों को उदार वित्तीय पैकेज देने की माँग की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रांतीय आपदा राहत फंड (एस.डी.आर.एफ.) में से खर्चों के लिए कोविड से सम्बन्धित शर्तें भी नरम करने की माँग रखी।

कोविड की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के ज़रिये हुई मीटिंग के दौरान कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक कोविड से सम्बन्धित खर्चों के लिए एस.डी.आर.एफ. में से इस समय पर 35 प्रतिशत तक फंड बरतने की शर्त है जबकि मौजूदा ज़रूरतों की पूर्ति के लिए यह काफी नहीं है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन भी मीटिंग में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने उत्तरी जोन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलौजी की स्थापना करने के लिए पंजाब के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर भारत सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए भारतीय मैडीकल अनुसंधान कौंसिल (आई.सी.एम.आर.) को इंस्टीट्यूट के लिए जल्दी ही 25 एकड़ ज़मीन सौंप दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं जो अब तक 24891 तक पहुँच गए हैं और 604 मौतें हुई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को यू.जी.सी. के 30 सितम्बर तक फ़ाईनल इम्तिहान लाज़िमी तौर पर करवाने के फ़ैसले की समीक्षा करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब, सितम्बर में परीक्षाऐं करवाने की स्थिति में नहीं होगा क्योंकि उस समय राज्य को कोविड के शिखर का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन विद्यार्थियों को उनकी पिछली कारगुज़ारी और अंदरूनी मूल्यांकन के आधार पर अगली क्लासों में भेजा जा सकता है और जो विद्यार्थी अपने कारगुज़ारी में सुधार लाना चाहते हैं, उनके बाद में इम्तिहान लेने की छूट दी जा सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से ऑनलाइन स्कूल शिक्षा ख़ास कर 11वीं और 12वीं कक्षा के गरीब विद्यार्थियों के लिए सहायता की माँग की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने के लिए बुनियादी ढांचा सृजन करने के लिए और फंडों की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि चाहे पंजाब कोविड के लिए 10 लाख (एक मिलियन) पीछे 23,000 टैस्ट कर रहा है जो राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक है और अगले 15 दिनों में आर.टी. -पी.सी.आर. टैस्ट 12000 से बढ़ा कर 20000 करने की योजना है। यह टेस्टिंग सामर्थ्य और बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चण्डीगढ़ और पंजाब में स्थित भारत सरकार की संस्थाओं को टेस्टिंग सामर्थ्य बढ़ाने की अपील की और इसके बारे वह पहले भी उनको पत्र लिख चुके हैं।

राज्य की 2.4 प्रतिशत मौत दर पर चिंता जाहिर करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि चाहे सभी भारत में एक मिलियन के पीछे होती मौतों की अपेक्षा यह कम है और मौतों के 91 प्रतिशत मामले सह - बीमारियों से सम्बन्धित हैं परन्तु यह अभी भी पड़ोसी राज्य हरियाणा की अपेक्षा अधिक हैं। उन्होंने कहा कि मरीज़ इलाज के लिए अस्पतालों में देरी से आ रहे हैं और 86 प्रतिशत मौतें ट्रशरी अस्पतालों में भी हो रही हैं। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बठिंडा में स्थित एमज़ में कोविड टेस्टिंग और इलाज तुरंत शुरू करने की अपील की जबकि इस संस्था में ओ.पी.डी. पहले ही कार्यशील है। उन्होंने कहा कि कोविड का इलाज शुरू करने से दक्षिणी पंजाब के लोगों को सहायता मिलेगी। उन्होंने संगरूर में स्थित पी.जी.आई. सैटेलाइट सैंटर में विशेष तौर पर कोविड के इलाज के लिए बिस्तरों के सामर्थ्य बढ़ाने की भी माँग की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को फ़िरोज़पुर में स्वीकृत किये पी.जी.आई. सैटेलाइट सैंटर का काम भी तुरंत करने की विनती की।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि पहले ही मंजूर किये तीन मैडीकल कालेजों में से मोहाली के मैडीकल कालेज में क्लासों इस साल से शुरू होने जाएंगी परन्तु ऐसी और संस्थाओं की ज़रूरत है। उन्होंने ज़रूरत आधारित जिलों गुरदसापुर, संगरूर /मलेरकोटला के साथ-साथ मोगा में नये कालेज स्थापित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोविड ने यह दिखा दिया है कि हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में सेहत सहूलतें और मज़बूत करने की जरूरत है।

राज्य में कोविड की स्थिति संबंधी जानकारी देते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बताया कि पिछले दो हफ़्तों में कोविड केस 500 से 1000 तक बढ़े हैं और पिछले पाँच दिनों की पॉजिटिव दर 8.73 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि चाहे सभी जिलों में केस बढ़ रहे हैं परन्तु लुधियाना, जालंधर और पटियाला शहरों से बड़ी संख्या में केस सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे अधिक प्रभावित जिलों में माईक्रो -कंटेनमैंट जोनों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने मीटिंग के दौरान बताया कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई और तेज़ करने के लिए राज्य ने दो प्लाज्मा बैंक (पटियाला और अमृतसर) कार्यशील कर दिए हैं और एक और बैंक जल्द ही फरीदकोट के सरकारी मैडीकल कालेज में खोला जा रहा है।

आई.पी.एल. चेयरमैन बृजेश पटेल ने बताया, यूएई में आई.पी.एल. कराने के लिए सरकार से मिली मंजूरी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में कराने के लिये केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। लीग के चेयरमैन बृजेश पटेल ने सोमवार को यह जानकारी दी। आईपीएल संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच शारजाह, दुबई और अबुधाबी में खेला जायेगा। सरकार ने पिछले सप्ताह बीसीसीआई को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। भारत में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के कारण यूएई में टूर्नामेंट कराया जा रहा है। पटेल ने कहा ,'' हमें लिखित मंजूरी मिल गई है।'' उनसे पूछा गया था कि क्या गृह और विदेश मंत्रालय दोनों ने लिखित में मंजूरी दे दी है। भारत का कोई भी खेल संगठन जब घरेलू टूर्नामेंट विदेश में कराता है तो गृह, विदेश और खेल मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है।

बोर्ड के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा ,'' सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हमने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का बता दिया था। अब हमें लिखित मंजूरी भी मिल गई है तो टीमों को सूचित किया जायेगा।'' अधिकांश टीमें 20 अगस्त के बाद रवाना होंगी।

आई.पी.एल. 2020 के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर चर्चा में पतंजलि का नाम

उन्हें रवानगी से पहले 24 घंटे के भीतर दो आरटी पीसीआर टेस्ट कराने होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स टीम 22 अगस्त को रवाना होगी जिसका चेपॉक स्टेडियम पर एक छोटा शिविर लगाया जायेगा। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से करार टूटने के बाद बीसीसीआई को प्रायोजन तलाशने में भी दिक्कत हो रही है।

यह 440 करोड़ रूपये का करार था जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर हुई हिंसक झड़प के कारण चीनी उत्पादों और कंपनियों के बहिष्कार की मांग के बीच इस साल के लिये रद्द कर दिया गया है। बाबा रामदेव की पतंजलि ने नया टाइटल प्रायोजक बनने में रूचि दिखाई है।

सिंगला द्वारा सरकारी स्कूलों में दाख़िले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बन्दिश ख़त्म करने की हिदायत

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

सरकारी स्कूलों में दाख़िले के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आ रही मुश्किल को गंभीरता से लेते हुए पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने दाखिले सम्बन्धी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बन्दिश ख़त्म करने के निर्देश दिए हैं जिससे विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में दाखिले के सम्बन्ध में कोई मुश्किल पेश न आए। इसकी जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि श्री सिंगला के निर्देशों के बाद विभाग ने इस सम्बन्ध में ज़िला शिक्षा अफसरों को एक पत्र जारी कर दिया है। प्रवक्ता के अनुसार सरकारी स्कूलों में दाखिले के सम्बन्ध में ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बन्दिश को ख़त्म कर दिया गया है और स्कूल मुखियों को ऐसे विद्यार्थियों को अपने स्तर पर दाख़िला देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही स्कूल मुखियों को निर्देश दिये गए हैं कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट न होने वाले विद्यार्थियों के माँ बाप से पढ़ाई के सम्बन्ध में लिखित तौर पर लिया जाये। प्रवक्ता के अनुसार ट्रांसफर सर्टिफिकेट न देने वाले स्कूलों के नाम मुख्य दफ्तर को भेजने के लिए भी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए हैं। इसके साथ ही दाखिला लेने की इच्छा रखने वाले जिन विद्यार्थियों के पास जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, उनको जन्म सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में मजबूर न करने के लिए भी हिदायतें जारी की गई हैं और इन विद्यार्थियों को प्रोवीजन आधार पर दाखिला देने के लिए कहा गया है।

जन्म सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में भी विद्यार्थियों को मजबूर न करने के आदेश जारी

कृषि से औद्योगिक क्षेत्र में भी पंजाब को अग्रणी राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध हैं-कैप्टन

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

औद्योगिक क्षेत्र में पंजाब को अग्रणी राज्य बनाने की अपनी वचनबद्धता दोहराते हुये मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने गुरूवार को कहा है कि वह चाहते हैं कि राज्य औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों में नेतृत्व करे और इसको तरक्की के रास्ते पर लेकर जाये।

वह वीडियो कान्फ्रेंस के द्वारा देश के प्रसिद्ध उद्योगपतियों के साथ दिन भर चली मीटिंग को संबोधन कर रहे थे जिसका नेतृत्व चण्डीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने किया। मुख्यमंत्री ने चण्डीगढ़ यूनिवर्सिटी का इस बात पर भी धन्यवाद किया कि उन्होंने कोविड के संकट के दौरान सबसे पहले अपने कैंपस को 1000 बिस्तरों का कोविड केयर सैंटर बनाने की पहल की और साथ ही सैनीटाईज़र, मास्क और अन्य ज़रूरी वस्तुएँ बाँटी।

पंजाब को औद्योगिक विकास के रास्ते पर ले जाने की अपनी दृढ़ता प्रकट करते हुये मुख्यमंत्री ने अपने जीवन काल में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने की इच्छा ज़ाहिर की जिससे राज्य की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि फ़िलहाल चिंता का विषय पंजाबियों के 'कोई बात नहीं' वाली लापरवाह धारणा के चलते टैस्ट और इलाज में देरी के कारण राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों का है। उन्होंने कहा कि हालाँकि यह एक अच्छी धारणा है परन्तु कोविड महामारी के मद्देनजर कुछ मामलों में यह नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले दिन में उन्होंने यही बात प्रधानमंत्री को भी कही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की अपेक्षा पंजाब की अधिक मौत दर इसी स्वभाव के कारण है क्योंकि पंजाबी अस्पताल जाने में तब तक देरी करते हैं जब तक लाज़िमी नहीं हो जाता। उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों को पंजाब आने और उनकी सरकार की तरफ से राज्य में बनाऐ औद्योगीकरण

माहौल का जायजा लेने का न्योता देते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि राज्य में उद्योग समर्थकी नीतियाँ, निर्विघ्न संपर्क व्यवस्था, उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचा, कौशल काम के साथ हुनर विकास और बेहतरीन प्लेसमेंट के मौके पर प्रदान करने वाली नामक शैक्षिक संस्थाओं ने पंजाब को निवेश के लिए उपयुक्त स्थान बनाया है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अफसोस जाहिर करते हुये कहा कि अकालियों ने पंजाबी राज्य लहर के द्वारा सिख बहुमत वाले राज्य की सृजना करने के लिए राज्य का पुनर्गठन करवाया और इनकी इस राजनीति की कीमत पंजाब को औद्योगिक पट्टी खोकर उतारनी पड़ी। उन्होंने आगे कहा कि पानी के संकट ने कृषि को भी प्रभावित किया है और राज्य को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। भूजल में गिरावट के चलते कृषि के अब टिकाऊ विकास का क्षेत्र न रहने के कारण उनकी सरकार ने औद्योगिक विकास को प्रौत्साहन देने के लिए मुहिम शुरू की हुई है। उन्होंने कहा कि नये नियमों से उद्योगों को रुकी हुई मंजूरियां मिलती हैं जिससे इस क्षेत्र में विकास करने में सुविधा हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाँच रुपए प्रति यूनिट बिजली, निवेश की आकर्षक संभावनाओं समेत विभिन्न रियायतें और नीतियाँ पंजाब में निवेश करने के लिए रास्ता खोलती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों के दौरान ज़मीनी स्तर पर 65000 करोड़ रुपए का निवेश और चार बड़े औद्योगिक पार्कों के आने से पंजाब पहले ही बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों के लिए अपनी बेमिसाल निवेश संभावनाओं की पेशकश करके अपने आप को सिद्ध कर चुका है। उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान भी राज्य को तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि लॉकडाऊन हटने के बाद प्रवासी मज़दूर बड़ी संख्या में लौट रहे हैं और लुधियाना में 2.34 लाख यूनिट पहले ही कार्यशील हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि राज्य और राज्य के उद्योगों ने हमेशा प्रवासी मज़दूरों का ख़्याल रखा है और हड़तालें, ट्रक यूनियनें आदि की अनुपस्थिति उद्योगों को उत्साहित कर रहे हैं।

महामारी के बीच न्यूजीलैंड फिर से शुरू करने जा रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, ये टीमें करेंगी दौरा

■ ऑकलैंड/ब्यूरो

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डेविड व्हाइट ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज ने पुष्टि की है कि वे आगामी गर्मियों में उनके देश का दौरा करेंगे। व्हाइट ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) उस तरह का जैव-सुरक्षित वातावरण तैयार करने में लगा है जैसा कि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कोरोना वायरस से प्रभावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए अपने मौजूदा सत्र में किया है।

उन्होंने 'ईएसपीएनक्रिकइंफो' से कहा, '' हम शानदार प्रगति कर रहे हैं। मैंने अभी फोन पर वेस्टइंडीज बात की है, वे यहां आने की पुष्टि कर रहे हैं। पाकिस्तान की पुष्टि की है, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ने भी दौरे के लिए हामी भरी है, ऐसे में हमारे पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के 37 दिन हैं।'' व्हाइट ने कहा कि महिलाओं की टीम सितंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी जबकि ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम फरवरी में न्यूजीलैंड आयेगी।

उन्होंने कहा, '' व्हाइट फर्न्स (न्यूजीलैंड महिला टीम) सितंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी और फिर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम फरवरी में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। हम अभी कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं लेकिन इसके पांच वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला होने की उम्मीद है।''

सोचना पड़ता है

अभी हंसी को भी चेहरे पर आने को सोचना पड़ता है हर बार,
कैसे आऊ यह तो होता नुहार भरा था हर बार,
पता नहीं कैसे चुपचाप,शांत सा हो कर रह गया अब,
यही सवाल मुझ से समय कर रहा था हर बार,
सुना आज कल बातें करता रहता दिले-ए-दर्द की,
फिर कैसे सहारता जो सितम दिया उसे था हर बार,
लगता गरुर हो गया होगा उसे अपने चाहने वालो पर,
करने लग पड़ा था एतबार बेहिसाब जिन से डरता था हर बार,
वक्त नहीं रुकता कभी किसी के लिए भरम था उसका,
फकीरा फिर उठ ठुकरा दे दर्द को हौंसला नहीं मरता हर बार,
अभी हंसी को भी चहरे पर आने को सोचना पड़ता है हर बार,
कैसे आऊ यह तो होता नुहार भरा था हर बार,

विनोद फकीरा, स्टेट आवोर्डे
आरिया नगर, करतारपुर
मोबाइल:098721-97326

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor: ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.